

झारखंड उच्च न्यायालय, राँची

सी. एम. पी. संख्या 415/2020

अजय प्रसाद सिंह, आयु लगभग 59 वर्ष, पिता- श्री परसु राम प्रसाद सिंह, निवासी- गौरीशंकर रोड, जुगसलाई, जमशेदपुर, डाकघर और थाना-जुगसलाई, जमशेदपुर, जिला पूर्वी सिंहभूम

..... याचिकाकर्ता

- बनाम -

1 ज्ञानेन्द्र कुमार सिंह, श्री श्याम बिहारी सिंह का पुत्र, सुखदेव नगर, पीओ-जीपीओ, पीएस-सुखदेव नगर, जिला राँची

..... उत्तरदाता / विपक्षी पक्ष संख्या 1

2. अब्दुल रब (अंजुम), अब्दुल राशिद का बेटा, क्रॉस रोड नंबर 1, हाउस नंबर 15, आजाद नगर, मानगो, पीओ और पीएस मानगो, जमशेदपुर, जिला - पूर्वी सिंहभूम

..... प्रोफोर्मा उत्तरदाता / प्रोफोर्मा विपक्षी संख्या 2

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री संजय कुमार द्विवेदी

याचिकाकर्ता के लिए:- श्री ए. के. साहनी, अधिवक्ता

विपक्षी पक्ष संख्या 1 के लिए श्री राहुल कुमार गुप्ता, अधिवक्ता

4/12.02.2021 याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वत वकील श्री ए. के. साहनी और प्रत्यर्थी/विपक्षी पक्ष संख्या 1 की ओर से उपस्थित विद्वत वकील श्री राहुल कुमार गुप्ता को सुना।

इस सी एम पी याचिका को कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न स्थिति को ध्यान में रखते हुए उच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों के मद्देनजर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की गई। किसी भी पक्ष ने ऑडियो-वीडियो की किसी भी तकनीकी गड़बड़ी के बारे में शिकायत नहीं की है और उनकी सहमति से इस मामले को सुना गया है।

एफ. ए. संख्या 292/2019 की बहाली के लिए यह सी एम पी दायर की गई है। उक्त एफ. ए. की बहाली के लिए यह सी एम पी दाखिल करने में 249 दिनों की देरी को माफ करने के लिए आईए संख्या 6348/ 2020 दाखिल की गई है, श्री साहनी, याचिकाकर्ता के विद्वत वकील ने कहा कि अनजाने में उनके कार्यालय ने आदेश पर ध्यान नहीं दिया है और यही कारण है कि देरी हुई है और यह पता चला है कि इसे दिनांक 20.12.2019 के आदेश का पालन नहीं करने के लिए खारिज कर दिया गया है और तत्काल कदम उठाया गया है और सी एम पी दायर किया गया है।

नोटिस के अनुसरण में, श्री राहुल कुमार गुप्ता, विरोधी पार्टी नं. १ की ओर से विद्वत वकील पहले ही पेश हो चुके हैं और वह निवेदन करते हैं कि २४९ दिनों का अत्यधिक विलंब हुआ है और याची की गलती के कारण यह मामला खारिज कर दिया गया है। सी एम पी में कोई योग्यता नहीं है। विरोधी पक्ष संख्या 2 पर नोटिस प्रभावी हो गया है।

पक्षकारों की ओर से पेश होने वाले विद्वान वकीलों को सुनने के बाद, यह स्पष्ट होता है कि सी एम पी दाखिल करने में देरी को माफ करने के लिए पर्याप्त कारण बनाए गए हैं और तदनुसार, सी एम पी दाखिल करने में 249 दिनों की देरी माफ की जाती है।

आईए संख्या 6348/ 2020 की अनुमति दी गई है और उसका निपटारा कर दिया गया है।

यह सी एम पी एफ. ए. संख्या 292/ 2019 की बहाली के लिए दाखिल किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि 20.12.2019 को एक अनिवार्य आदेश जारी किया गया था और उस आदेश का अनुपालन न करने के कारण उक्त एफ. ए. को खारिज कर दिया गया था।

श्री साहनी के निवेदन को ध्यान में रखते हुए, याची के विद्वत वकील ने कहा कि असावधानी के कारण उसके कार्यालय ने आदेश पर ध्यान नहीं दिया है और यही कारण है कि कथित एफ. ए. को खारिज कर दिया गया था, न्यायालय को उक्त एफ. ए. को बहाल करने के लिए पर्याप्त कारण है।

तदनुसार, 2019 की एफ. ए. संख्या 292 को इसकी मूल फाइल में बहाल कर दिया गया है।

यह सीएमपी की अनुमति दी जाती है और उसका निपटारा कर दिया जाता है।

(संजय कुमार द्विवेदी , न्याया0)